नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 117
दि. 30.01.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

देश की अर्थव्यवस्था का आईना: संसद में पेश आर्थिक सर्वे ने दिखाई मजबूती, चुनौतियां और भविष्य की राह

(जीएनएस)। नई दिल्ली में संसद का माहौल उस समय गंभीर और अर्थपूर्ण हो गया, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का 'आर्थिक रिपोर्ट कार्ड' यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। यह दस्तावेज सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि भारत की मौजूदा आर्थिक सेहत, आम आदमी की रोजमर्रा की स्थिति और आने वाले वर्षों की संभावनाओं की तस्वीर पेश करता है। प्रश्नकाल समाप्त होते ही वित्त मंत्री ने जैसे ही सर्वे सदन के पटल पर रखा, साफ हो गया कि यह बजट से पहले देश की दिशा और दशा तय करने वाला सबसे अहम दस्तावेज है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जरूरी कागजात सदन में रखवाए और दिनभर की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन आर्थिक सर्वे में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा का सिलसिला देशभर में शुरू हो गया।

आर्थिक सर्वे के मुताबिक वैश्विक तनाव, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। यह संकेत देता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए रखने में सफल हो रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिए भी विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से भी थोड़ा अधिक है। यह मजबूती सरकार द्वारा किए गए ढांचागत सुधारों, निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों और घरेलू मांग के सहारे संभव हो पाई है।

महंगाई को लेकर भी सर्वे में राहत भरी तस्वीर सामने आई है। आरबीआई और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में महंगाई नियंत्रण में रहेगी और यह 4 प्रतिशत के तय लक्ष्य के आसपास बनी रहेगी। अच्छी खरीफ और रबी फसलों के चलते खाद्य महंगाई पर दबाव कम हुआ है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि सर्वे यह भी संकेत देता है कि वैश्विक हालात बिगड़ने पर ऊर्जा और आयातित वस्तुओं की कीमतें फिर दबाव बना सकती हैं, ऐसे में सतर्कता जरूरी होगी। रोजगार के मोर्चे पर आर्थिक सर्वे ने एक ओर उम्मीद जगाई है तो दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी सामने रखी हैं। सर्वे के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 56.2 करोड़ लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में ही 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं, जो यह बताता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार का फायदा रोजगार बाजार तक पहुंच रहा है। टैक्स सुधारों, श्रम कानूनों में बदलाव और स्टार्टअप व गिग इकोनॉमी के

विस्तार ने नौकरियों के नए अवसर खोले हैं। लेकिन इसी गिग इकोनॉमी को लेकर सर्वे ने एक गंभीर चेतावनी भी दी है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 40 प्रतिशत गिग वर्कर्स की मासिक कमाई 15 हजार रुपये से कम है। यह स्थिति सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम आय जैसे सवाल खड़े करती है। इसी वजह से सर्वे में सुझाव दिया गया है कि गिग वर्कर्स के लिए प्रति घंटे या प्रति टास्क न्यूनतम कमाई तय की जानी चाहिए और काम के इंतजार के समय का भी भुगतान हो।

खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर सर्वे अपेक्षाकृत सकारात्मक नजर आता है। कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026 में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिकॉर्ड 3,320 लाख टन अनाज उत्पादन ने न सिर्फ देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत की है, बल्कि महंगाई को काबू में रखने में भी अहम भूमिका निभाई है। सरकार का फोकस अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आय सुरक्षा, बेहतर भंडारण व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने पर भी है। सर्वे यह साफ करता है कि अगर कृषि को आधुनिक तकनीक और बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ा गया, तो ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदल सकती है। राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर सरकार ने खुद की पीठ थपथपाने लायक उपलब्धि हासिल की है। आर्थिक सर्वे बताता है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय घाटा कम करने के लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8 प्रतिशत रहा और इसे वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। घाटे में यह कमी निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है और ब्याज दरों व महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। हालांकि सर्वे ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता भी जताई है। खासतौर पर लोकलुभावन योजनाओं और बिना शर्त नकद अंतरण योजनाओं पर बढ़ते खर्च से राज्यों का राजस्व घाटा बढ़ रहा है, जिसका असर देश की उधारी लागत पर पड़ सकता है।

विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह भंडार न सिर्फ रुपये को स्थिरता देता है, बल्कि किसी भी वैश्विक झटके से निपटने की क्षमता भी बढ़ाता है। निर्यात के क्षेत्र में भी भारत ने चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। अमेरिका द्वारा ऊंचे टैरिफ लगाए जाने और वैश्विक व्यापार में सुस्ती के बावजूद भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 825.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

इसके पीछे सरकार की नई व्यापार रणनीति है, जिसके तहत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों के साथ समझौते किए गए हैं।

आर्थिक सर्वे ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर भी साफ शब्दों में चिंता जताई है। सर्वे में सलाह दी गई है कि भारत में स्कूली शिक्षा की औसत अवधि को मौजूदा 13 वर्षों से बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाना चाहिए। सर्वे बताता है कि 2047 तक भी देश की बड़ी आबादी स्कूली उम्र में रहेगी, ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता और अवधि दोनों बढ़ाना जरूरी है। इसी तरह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की बढ़ती खपत और बच्चों में मोटापे के मामलों पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। सर्वे ने ऐसे खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है, ताकि भविष्य की पीढ़ी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके।

बुनियादी

देश किसी नई विभाजन रेखा का बोझ नहीं उठा सकता

UGC पर सुप्रीम रोक के बाद बोले कुमार विश्वास

(जीएनएस)। नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद देश की बौद्धिक और सामाजिक बहस एक बार फिर केंद्र में आ गई है। इस फैसले का स्वागत करते हुए कवि और सामाजिक चिंतक कुमार विश्वास ने कहा है कि भारत इस समय किसी भी तरह के नए विभाजन को झेलने की स्थिति में नहीं है और ऐसे दौर में राजनीति और सरकारों को भी बेहद संतुलित और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस संवेदनशीलता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों की मनोदशा को समझा है, उसी तरह राजनीति भी इस मुद्दे का कोई सकारात्मक और समावेशी समाधान निकालेगी। कुमार विश्वास ने कहा कि यह सच है कि भारत के सामाजिक इतिहास में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों ने सदियों तक अन्याय और उत्पीड़न झेला है और उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करना और उसके समाधान के लिए कदम उठाना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी प्रक्रिया में कोई निर्दोष न फंसे और किसी भी जाति, वर्ग या धर्म

का व्यक्ति अपने ही देश में असहज महसूस न करे। उनका कहना था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर किसी नए भय या असुरक्षा की भावना को जन्म देने लगे, तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है।

उन्होंने कहा कि पिछले एक हजार वर्षों में भारत की सामाजिक संरचना पर कई बाहरी और आंतरिक प्रभाव पड़े हैं, जिनकी वजह से जाति और भेदभाव जैसी समस्याएं और गहरी हुईं। इन समस्याओं से मुक्ति के प्रयास पिछले कई दशकों से किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, लेकिन समाधान ऐसा होना चाहिए जो समाज को जोड़ने वाला हो, न कि नई दीवारें खड़ी करने वाला। कुमार विश्वास ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में अगर छात्र अपने विचारों और पहचान को लेकर भय या संकोच में जीने लगें, तो यह देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने विशेष रूप से आभार जताते हुए कहा कि अदालत ने केवल कानूनी पहलू ही नहीं देखा, बल्कि समाज पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को भी समझा। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणियों से यह साफ है कि न्यायपालिका को इस बात की चिंता है कि कहीं शिक्षा संस्थान सामाजिक विभाजन का केंद्र न बन जाएं। कुमार विश्वास ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मन को मुक्त करना और समाज को जोड़ना होता है, न कि डर और संदेह का वातावरण बनाना।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है और यह कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर कर देती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि फिलहाल 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

नए यूजीसी नियमों को लेकर देशभर में पिछले कुछ दिनों से विरोध देखने को मिल रहा था, खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के बीच यह आशंका गहराती जा रही थी कि नियमों की भाषा अस्पष्ट होने के कारण इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणियों में कहा कि अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो इसके खतरनाक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं और समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि भारत की एकता और विविधता का प्रतिबिंब उसके शिक्षण संस्थानों में दिखना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों में यह अनिवार्य किया गया था कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बनने वाली संबंधित समितियों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के साथ-साथ दिव्यांग और महिला सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।

कर्तव्य, साहस और समर्पण की मिसाल बने अनवर हुसैन, आरपीएफ उप निरीक्षक को राष्ट्रपति पुलिस पदक से राष्ट्रीय सम्मान

(जीएनएस)। वडोदरा। रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास में यह क्षण गर्व और प्रेरणा से भरा है, जब वडोदरा मंडल में कार्यरत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उप निरीक्षक अनवर हुसैन को उनकी सराहनीय, निष्ठावान और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 'इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान की पहचान है, बल्कि यह रेलवे सुरक्षा बल की उस समर्पित सेवा भावना का भी प्रतीक है, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति की रक्षा में सतत रूप से लगी रहती है।

उप निरीक्षक अनवर हुसैन ने अपने पूरे सेवाकाल के दौरान कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी को अपने कार्य का मूल आधार बनाया। रेलवे जैसे विशाल और जटिल तंत्र में, जहां हर दिन हजारों ट्रेनें और करोड़ों यात्री आवाजाही करते हैं, वहां सुरक्षा सुनिश्चित करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण दायित्व है। अनवर हुसैन ने इस चुनौती को पूरी गंभीरता और सजगता के साथ निभाया। यात्रियों की सुरक्षा, महिला एवं बच्चों की संरक्षा, रेलवे परिसंपत्तियों की चोरी रोकने, असामाजिक

तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण तथा आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई जैसे अनेक मोर्चों पर उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उनकी कार्यशैली हमेशा शांत, संतुलित और परिणामोन्मुख रही है। कई अवसरों पर उन्होंने जोखिम उठाकर यात्रियों की जान बचाई और रेलवे संपत्ति को नुकसान से सुरक्षित रखा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान उन्होंने न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित किया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया। यही कारण है कि वे अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आम यात्रियों के बीच भी सम्मान और विश्वास का प्रतीक बन गए। रेलवे सुरक्षा बल के मूल उद्देश्य—"यात्री सुरक्षा सर्वोपरि"—को अनवर हुसैन ने केवल नारे के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतारकर दिखाया। उनकी सतर्कता और सजगता के चलते कई संगठित चोरी गिरोहों का पर्दाफाश हुआ, वहीं रेलवे परिसरों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाया गया। उनकी सेवाएं केवल ड्यूटी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को भी पूरी निष्ठा से निभाया। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला 'इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस' देश के सुरक्षा बलों में कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान असाधारण समर्पण, अनुकरणीय आचरण और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। उप निरीक्षक अनवर हुसैन का इस सम्मान के लिए चयन इस बात का प्रमाण है कि उनका कार्य केवल स्थानीय या विभागीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है।

यह सम्मान वडोदरा मंडल और सम्पूर्ण रेलवे सुरक्षा बल के लिए भी गर्व का विषय है। इससे आरपीएफ के अन्य अधिकारियों और जवानों का मनोबल बढ़ेगा और वे भी और अधिक उत्साह, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित होंगे। यह उपलब्धि यह संदेश देती है कि ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता कभी अनदेखी नहीं रहती और राष्ट्र ऐसे सेवाभावी कर्मियों को समय पर सम्मानित करता है। रेलवे सुरक्षा बल देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आरपीएफ के जवान दिन-रात यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उप निरीक्षक अनवर हुसैन जैसे अधिकारी इस बल की आत्मा हैं, जो अपने आचरण और कार्य से यह सिद्ध करते हैं कि वर्दी केवल एक पहचान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक है।

उनकी इस उपलब्धि पर वडोदरा मंडल के अधिकारियों, सहकर्मियों और रेलवे परिवार में हर्ष का माहौल है। सभी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि उनका यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। यह सम्मान यह भी दर्शाता है कि समर्पित सेवा, अनुशासित जीवन और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर सकता है।

वंदे मातरम की गूंज से कर्तव्य पथ तक, गुजरात की झांकी ने चौथी बार जनता का दिल जीता

(जीएनएस)। गांधीनगर । 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात की झांकी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदे मातरम' थीम पर आधारित गुजरात की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड की 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देशभर से आए दर्शकों और ऑनलाइन मतदान में भाग लेने वाले लाखों नागरिकों के बीच इस झांकी ने विशेष आकर्षण और उत्सुकता पैदा की। गुजरात की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गुजरात की झांकी में राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जिस प्रभावशाली और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसी के कारण उसे जनता का व्यापक समर्थन और सराहना मिली। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है कि गुजरात की झांकी ने नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में लगातार चौथे साल 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संदेश में कहा कि 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदे मातरम' थीम पर आधारित झांकी ने देशवासियों के मन में गहरी छाप छोड़ी है। इस झांकी में देशभक्ति की भावना के साथ-साथ गुजरात के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महान सेनानियों की भूमिका को

जीवंत रूप में दिखाया गया, जिसे लोगों ने दिल से सराहा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले गुजरात की झांकी ने वर्ष 2023, 2024 और 2025 में भी लगातार तीन वर्षों तक इस प्रतिष्ठित श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता था। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा माईगॉव पोर्टल पर 26 जनवरी से 27 जनवरी की रात 11 बजकर 45 मिनट तक आयोजित ऑनलाइन मतदान में गुजरात की झांकी पहले घंटे से लेकर मतदान समाप्त होने तक लगातार अग्रणी रही। कुल प्राप्त मतों में से 43 प्रतिशत वोट गुजरात की झांकी को मिले, जिसके साथ उसने 'पीपुल्स चॉइस' कैटेगरी में स्पष्ट बढ़त बनाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इस मतदान में दूसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को मात्र 9 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जबकि शेष 15 राज्यों की झांकियों को अपेक्षाकृत कम प्रतिशत में मत मिले।

इस वर्ष कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत गुजरात की झांकी का निर्माण राज्य के सूचना विभाग द्वारा किया गया था। झांकी में 'वंदे मातरम' और स्वदेशी आंदोलन की भावना से जन्मी स्वतंत्रता की क्रांति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र तक की यात्रा को अत्यंत प्रभावशाली और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। झांकी ने यह संदेश दिया कि किस तरह आजादी की चेतना से प्रेरित भारत आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की राह पर आगे बढ़ रहा है।

गुजरात की झांकी की 'पॉपुलर चॉइस' श्रेणी में अग्रणी परंपरा की शुरुआत वर्ष 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड से हुई थी। उस वर्ष 'क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात' थीम पर आधारित झांकी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात की अग्रणी भूमिका और प्रधानमंत्री के स्वच्छ व हरित ऊर्जा के आह्वान को दर्शाया गया था, जिसे जनता ने भरपूर समर्थन दिया।

इसके बाद वर्ष 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में 'धोरडो–वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज' थीम पर आधारित गुजरात की झांकी ने भी 'पॉपुलर चॉइस' कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। यही नहीं, उसी वर्ष चयन समिति यानी ज्यूरी चॉइस में भी गुजरात की झांकी को द्वितीय स्थान मिला, जिससे राज्य की प्रस्तुति की गुणवत्ता और प्रभाव का अंदाजा लगाया गया।

वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गुजरात के आधुनिक विकास की तेज रफ्तार यात्रा को प्राचीन विरासत के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत 'आनर्तपुर से एकतानगर तक–विरासत से विकास का अद्भुत संगम' थीम वाली झांकी को भी 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' से नवाजा गया। इस झांकी ने विकास और संस्कृति के संतुलन का सशक्त संदेश दिया था।

इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदे मातरम' थीम पर आधारित गुजरात की झांकी को लगातार चौथी बार 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' मिलने से राज्य की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। यह सफलता न केवल गुजरात की रचनात्मक प्रस्तुति की जीत है, बल्कि देशवासियों के साथ उसके भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रमाण है।

उल्लेखनीय है कि आगामी 30 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के दौरान केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री की उपस्थिति में गुजरात राज्य को यह प्रतिष्ठित 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा। यह समारोह गुजरात के लिए गर्व और सम्मान का एक और महत्वपूर्ण क्षण साबित होगा।

संपादकीय

महाराष्ट्र में खलेगी अजित पवार की कमी

बुधवार सुबह बारामती के पास हुई एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार व चालक दल के सदस्यों समेत पांच लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मुंबई से बारामती आ रहा चार्टर विमान मौसम की खराबी के कारण रनवे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का असली पता जांच के बाद ही चलेगा, मगर प्रथम दृष्टया धुंध के कारण दृश्यता में कमी ही बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में छह बार उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार के राज्य में राजनीतिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता। राज्य में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य विपक्षी दलों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। हालांकि, ममता बनर्जी ने उनकी मौत को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु व चाचा शरद पवार ने उनकी मृत्यु को लेकर राजनीतिक बयानबाजी को खारिज किया है। निश्चय ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजित पवार की असामयिक दुर्घटना में मृत्य ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य जरूर पैदा कर दिया है। वहीं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के मुताबिक दुर्घटना क्रैश लैंडिंग के दौरान हुई। रनवे के निकट हुए हादसे में विमान में आग लग गई और स्थानीय लोगों के प्रयासों के बावजूद किसी को बचाया नहीं जा सका। विमान लियरजेट-45 सोलह साल पुराना था। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। निस्संदेह, अजित पवार जनता के नेता थे और जमीनी स्तर पर लोगों से उनका गहरा जुड़ाव था। बताया जाता है कि प्रशासनिक मामलों में उनकी समझ गहरी थी। वे वंचित वर्ग को सशक्त करने के प्रयासों के लिये जाने जाते रहे हैं।

बहरहाल, अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बदलते दांव-पेचों के लिये याद किया जाता रहेगा। उनके बारे में कहा जाता रहा है कि वे उस कहावत को हकीकत बनाते रहे हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही स्थायी दुश्मन। वे अपनों के साथ तो रहे, गैरों को भी रास आए। उन्होंने चाचा और अपने राजनीतिक गुरु शरद पवार से राजनीति के गुर सीखे। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता रहा है, लेकिन अजित पवार ने उनसे अलग होकर अपनी नई राह भी बनायी। यूं तो उन्होंने चाचा शरद के साथ राजनीतिक पारी शुरू की लेकिन साल 2023 आने तक वे एकला चलो की राजनीति करने लगे। हालांकि, उन्होंने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखा लेकिन एक समय वे पार्टी का सिंबल भी ले जाने में कामयाब रहे। फिर शरद पवार को नई पार्टी बनाकर उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। बारहवीं तक पढ़ाई के बावजूद वे अनुभवी नीतिकारों की सहायता से एक बेहतर प्रशासक भी साबित हुए। सहकारी चीनी मिलों से राजनीति की शुरुआत करने वाले पवार विधायक से लेकर सांसद तक चुने जाते रहे। वे राज्य में छह बार उप मुख्यमंत्री बने। साल 1991 में पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, लेकिन चाचा शरद पवार के लिये बाद में सीट खाली भी की। वे सबसे पहले 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। उनकी लोकप्रियता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वे सात बार विधायक चुने गए। फिर वे विलासराव देशमुख की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में पहली बार सिंचाई मंत्री बने। फिर ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। बाद में वे एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन में जल संसाधन मंत्री भी रहे। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उनके अचानक भाजपा गठबंधन के साथ आने और उप मुख्यमंत्री बनने ने सबको चौंकाया था। फिर पवार साल 2023 में महायुति गठबंधन का हिस्सा बनकर पांचवीं बार उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि, एनसीपी में विभाजन के बाद शरद पवार परिवार से संबंध बनाये रखे। इसके बावजूद कि उन्होंने एनसीपी का नाम और सिंबल तक ले लिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार को कई मायनों में हमेशा याद किया जाएगा।

अच्छी-सच्ची पत्रकारिता की कसौटी पर खरे उतरे मार्क

> “किसी भी पत्रकार के लिए मार्क टली जैसा विश्वास पाना किसी तमगे से कम नहीं है। वैसे उन्हें तमगे भी कम नहीं मिले– भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया और इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें 'सर' का खिताब दिया।

यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि मुझे बीबीसी के भारत स्थित संवाददाता स्वर्गीय मार्क टली से मिलने का कभी अवसर नहीं मिला, पर हकीकत यह भी है कि मैं पिछले चार-पांच दशकों में उनसे अक्सर मिलता रहा हूं। यह मिलना बीबीसी रेडियो के माध्यम से होता था। दशकों से रेडियो बीबीसी विश्वसनीय खबरों का एक पर्याय बन चुका हुआ था, और मेरे जैसे लाखों-करोड़ों श्रोता बीबीसी के माध्यम से ही खबरों की विश्वसनीयता परखा करते थे। बीबीसी को यह श्रेय जहां संस्थान की रीति-नीति के कारण मिलता था, वहीं सर मार्क टली जैसे सजग और ईमानदार पत्रकारों ने बीबीसी की विश्वसनीयता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

आज मार्क टली हमारे बीच नहीं हैं। भारत में ही जन्मे सर टली के निधन से ईमानदार पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे बीच से उठकर चला गया। वे चाहते थे कि उनका निधन भारत में ही हो और यह संयोग मात्र नहीं है कि भारत के बनते इतिहास का यह साक्षी अपनी जन्मभूमि से ही विदा हुआ। आज जब रेडियो के माध्यम से समय की सच्चाई जानने वाले श्रोता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ ही उस पत्रकारिता की बात भी होनी चाहिए, जिसके लिए वह जाना जाता रहा। और यह अवसर इस बात का भी है कि हम पत्रकारिता, विशेषकर भारत की पत्रकारिता के बारे में भी सोचें, यह आकलन करने की कोशिश करें कि आज हमारी पत्रकारिता की स्थिति क्या है, और जैसी है, वैसी क्यों है? अच्छी और सच्ची पत्रकारिता की शायद सबसे बड़ी कसौटी यह है कि विश्वसनीयता के संदर्भ में वह कहां ठहरती है। था एक ज़माना जब यह माना जाता था कि अखबार में यदि कुछ छपा है तो वह सही ही होगा, जो अखबार जितनी ज़्यादा तटस्थ और सही खबरें देता था, वह उतना ही बेहतर माना जाता था। अब जबकि अखबार के साथ टेलीविजन और सोशल मीडिया भी खबरों की दुनिया का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा कहा जाना चाहिए, बन गया है, तो विश्वसनीयता का महत्व और बढ़ जाता है। जिसकी जितनी ज़्यादा पहुंच है, उससे उतनी ही ज़्यादा ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। यह ईमानदारी ही मीडिया के कद को नापती है।

मुझे याद है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हुई तो राजीव गांधी दिल्ली से बाहर (बंगाल में) थे। तब उन्होंने बीबीसी रेडियो के माध्यम से ही समाचार की पुष्टि की थी। ज्ञातव्य है कि ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) ने तो शाम छह बजे तक उनकी मृत्यु की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। कारण कुछ भी बताये जायें, पर यह हकीकत अपनी जगह है कि राजीव गांधी को तब इंग्लैंड का बीबीसी रेडियो ही विश्वसनीय लगा था। यह तथ्य जहां बीबीसी के महत्व को दर्शाता है, वहीं इस बात को भी रेखांकित करता है कि मीडिया की विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह दुर्भाग्य ही है कि आज हमारा रेडियो सरकारी सूचनाओं का भोंपू बनकर रह गया है! दुर्भाग्य यह भी है कि आज हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा विश्वसनीयता के संकट का शिकार हो गया है।

लगभग आधी सदी पहले जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो उसका सबसे बुरा असर मीडिया पर ही पड़ा था। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गयी थी, कुछ भी छापने से पहले सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेनी होती थी। उस कठिन समय में जिन गिने-चुने साहसी पत्रकारों ने सरकार के इस आदेश का पालन करने से इनकार किया, उनमें बीबीसी रेडियो के भारत स्थित संवाददाता मार्क टली का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। तब उन्हें चौबीस घंटे में भारत छोड़कर जाने का आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था। सरकार के आगे घुटने टेकने के बजाय मार्क टली ने अपने देश लौट जाना बेहतर समझा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए वे इंग्लैंड लौट गये। पर सरकार उनकी वाणी पर प्रतिबंध नहीं लगा पायी थी। लंदन में रहते हुए भी वह भारत स्थित अपने सूत्रों से सही सूचनाएं प्राप्त करते रहे— भारत समेत दुनिया भर के श्रोताओं तक उन्हें पहुंचाते रहे।

यह सही है कि उस काल की भारत की पत्रकारिता पर अपयश के काले धब्बे लगे थे। आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने तब कहा था, 'जब हमारे पत्रकारों को घुटने टेकने के लिए कहा गया तो वे रेंगने लगे थे।' पर सच यह भी है कि उस स्थिति के लिए सिर्फ पत्रकार ही दोषी नहीं थे, पत्रकारों से कहीं ज़्यादा डर तब मीडिया-मालिकों, प्रबंधकों को था। लेकिन यह कथित विवशता आपातकाल में हमारी पत्रकारिता पर लगे धब्बों को नहीं मिटा सकती। दुर्भाग्य की बात तो यह भी है कि आज भी हमारी पत्रकारिता पर विश्वसनीयता का संकट मंडरा रहा है। मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज 'गोदी मीडिया' कहलाता है। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है।

बीबीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी मार्क टली ने भारत को ही अपना देश बनाया। वे भारत और भारत की चुनौतियों को अच्छी तरह समझते थे, और उनका मानना था कि जनता तक सही और समुचित जानकारी पहुंचाना पत्रकारिता का दायित्व है। उनका स्पष्ट कहना था कि पत्रकारिता का एक ही नियम है– अपने आप से यह पूछिए कि कोई आप पर क्यों विश्वास करता रहे। यदि आप दिमाग में यह सवाल बनाए रखेंगे तो स्वयं ही पता चल जाएगा कि आप रिपोर्ट कैसे करें। एक बार यदि विश्वास टूट जाये तो फिर से प्राप्त करना लगभग असंभव है। जितना आप सत्ता के निकट रहेंगे, इस विश्वास पर उतना अधिक जंग लगेगा।

पत्रकार टली सत्ता के नहीं, जनता के निकट रहना पसंद करते थे। उनकी संवेदना जनता के ही निकट रहती थी, पर इस बात का भी ध्यान उन्हें हमेशा रहा कि संवेदना भावुकता का रूप न ले ले। जनता से उनकी निकटता का यह परिणाम था कि जनता के मूड या भावना को वह आसानी से समझ जाते थे। उनके साथी पत्रकार अक्सर उनके इस गुण की चर्चा किया करते थे। यह जनता से उनकी निकटता का ही परिणाम (या प्रमाण) है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक दौरे के दौरान एक ग्रामीण ने उनके साथियों से कहा 'टली साहब कह रहे हैं तो सच ही होगा!' किसी भी पत्रकार के लिए इस तरह का विश्वास पाना अपने आप में किसी तमगे से कम नहीं है। वैसे उन्हें तमगे भी कम नहीं मिले– भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया और इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें 'सर' का खिताब दिया। दो सरकारों द्वारा इस तरह से सम्मानित करना अपने आप में एक विशेष उपलब्धि से कम नहीं है, पर सर मार्क टली के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार अपने पाठकों-श्रोताओं का विश्वास प्राप्त करना था। इस तरह विश्वास अर्जित करने वाले पत्रकार कम ही होते हैं। यह विश्वास ही सच्ची-अच्छी पत्रकारिता की पहचान है।

प्रेरणा

धीरे-धीरे बनती पहचान का सत्य

एक बार एक युवक अपने भीतर सवालों का तूफ़ान लिए एक शांत आश्रम पहुँचा। बाहर से देखने पर वह सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से लड़ रहा था। उसकी शिकायत किसी और से नहीं, किस्मत से भी नहीं थी, बस यही कसक थी कि वह जितनी मेहनत करता है, उतनी पहचान उसे नहीं मिलती। उसे लगता था कि वह लगातार आगे बढ़ रहा है, फिर भी दुनिया की नज़र में ठहरा हुआ है। उसी बेचैनी को शब्दों में बाँधते हुए उसने वृद्ध साधु से कहा कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन लोग मुझे देखते ही नहीं।

साधु ने उसकी बात पूरी सुनी। न टोका, न समझाने की जल्दी की। बस उसे साथ चलने को कहा। दोनों आश्रम के पीछे एक खुले स्थान में पहुँचे, जहाँ एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी छाया ठंडी थी। साधु ने ज़मीन पर पड़े एक छोटे से बीज की ओर इशारा किया और पूछा—यह बीज अभी किसी काम का नहीं लगता, न यह दिखता है, न इससे कोई लाभ मिलता है। क्या इसका मतलब यह है कि यह बेकार है?

युवक कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा कि जवाब तो साफ़ है, लेकिन फिर भी कुछ अंदर अटका हुआ था। साधु ने कहा—हर वह चीज़ जो मूल्यवान होती है, पहले अदृश्य रहती है। जो तुरंत दिखाई देने लगे, वह अक्सर कच्ची होती है। बीज को देखो, वह सबसे पहले खुद को मिट्टी के अंधेरे में छुपाता है। वहाँ कोई तारीफ़ नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता, बस धैर्य होता है और इंतज़ार।

साधु ने समझाया कि असली विकास हमेशा भीतर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया में जो शोर सुनाई देता है, जो चमक दिखती है, वह अक्सर भ्रम होती है। शक्ति वहाँ होती है जहाँ सन्नाटा होता है। जड़ें जब तक गहरी नहीं होतीं, पेड़ ऊँचाई की बात ही नहीं करता। अगर कोई पेड़ जल्दी बड़ा होने की ज़िद करे, तो पहली आँधी ही उसे गिरा देती है।

युवक को अपनी ही ज़िंदगी का प्रतिबिंब दिखने लगा। वह भी तो लगातार ऊपर दिखने की कोशिश में लगा था। उसे लग रहा था कि अगर लोग उसकी मेहनत देख लें, उसका नाम जान लें, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि शायद अभी उसका समय जड़ें फैलाने का है, शाखाएँ दिखाने का नहीं। साधु बोले—तुम्हारी बेचैनी पहचान की नहीं है, तुम्हारी बेचैनी अधीरता की है। पहचान धैर्य का फल होती है, माँगने से नहीं मिलती।

साधु ने आगे कहा कि जीवन में हर किसी की गति अलग होती है। कोई जल्दी फल देता है, कोई देर से। जो जल्दी फल देता है, उसका फल अक्सर कम समय का होता है। लेकिन जो देर से फलता है, वह पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। प्रकृति किसी से तुलना नहीं करती। वह हर बीज को उसका समय देती है। इसी वजह से प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है।

युवक ने पहली बार महसूस किया कि उसकी थकान मेहनत से नहीं, अपेक्षाओं से थी। वह हर दिन यह गिनता था कि उसे कितना मिला, न कि यह कि वह कितना बना। साधु ने कहा—अगर तुम रोज़ खुद को थोड़ा बेहतर बना रहे हो, तो तुम आगे बढ़ रहे हो, चाहे दुनिया तुम्हें अभी देखे या नहीं। दिखाई देना सफलता का प्रमाण नहीं होता, टिक पाना असली परीक्षा होती है।

साधु ने धैर्य को कमजोरी नहीं, शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि धैर्य वह साहस है जो इंसान को बिना ताली के चलते रहने की ताक़त देता है। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है, जब बाकी सब जल्दी में टूट रहे होते हैं। जो लोग शोर में आगे आते हैं, वे अक्सर शोर के साथ ही गायब हो जाते हैं। लेकिन जो लोग चुपचाप खुद को गढ़ते हैं, वे देर से सही, लेकिन स्थायी रूप से सामने आते हैं।

आज की दुनिया का उदाहरण देते हुए साधु ने कहा कि अब हर कोई जल्दी दिखना चाहता है। सोशल मीडिया पर हर पल खुद को साबित करने की होड़ है। लेकिन यह होड़ इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जब पहचान मेहनत से पहले आ जाती है, तो वह बोझ बन जाती है। इंसान उसे संभाल नहीं पाता। इसके उलट जब मेहनत पहचान से पहले आती है, तो पहचान अपने आप संभल जाती है।

युवक ने महसूस किया कि वह अब तक दूसरों की रफ़्तार देखकर अपनी रफ़्तार तय कर रहा था। साधु बोले—तुम्हारा रास्ता किसी और के रास्ते से नहीं नापा जा सकता। हर जीवन का अपना मौसम होता है। कोई बसंत में खिलता है, कोई शरद में फल देता है। समय से पहले खिलने की ज़िद फूल को भी मुरझा देती है।

साधु ने अंत में कहा—समय से पहले निकली टहनी टूट जाती है, और धैर्य से पली जड़ें तूफ़ान में भी खड़ी रहती हैं। यही जीवन का सत्य है। अगर आज तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तो यह मत समझो कि तुम गलत हो। शायद तुम बन रहे हो। और जो बन रहा होता है, वह अक्सर खामोश होता है।

युवक ने साधु को प्रणाम किया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन मन भरा हुआ था। उसे कोई तुरंत समाधान नहीं मिला था, लेकिन उसे दिशा मिल गई थी। अब वह पहचान के पीछे नहीं, तैयारी के साथ चलने वाला था। वह जान गया था कि धैर्य कोई इंतज़ार नहीं, एक सक्रिय साधना है। और इसी साधना में असली शक्ति जन्म लेती है।

वह आश्रम से लौटा, लेकिन अब उसकी चाल बदली हुई थी। कदम धीमे थे, लेकिन विश्वास से भरे थे। उसे अब जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जब समय आएगा, तो दुनिया खुद उसकी ओर देखेगी।

मोबाइल के दौर में मर्यादा की मिसिंग फाइल

एक वक्त था जब घर की दहलीज़ पार करते ही इंसान अपने आप छोटा हो जाया करता था। बाहर चाहे जितना बड़ा अफसर हो, घर में कदम रखते ही सिर्फ बेटा होता था। पिता का होना किसी पद या रिश्ते का नाम नहीं था, वह एक व्यवस्था थी। उनकी मौजूदगी में घर अपने आप संतुलन में आ जाता था। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आंखों का उठना और खांसी का एक हल्का सा स्वर ही काफी होता था। उस जमाने में पिता का डर नहीं, उनका वजन होता था। वही वजन बच्चों को सीधा रखता था, वही वजन उन्हें गिरने से पहले संभाल लेता था।

आज हालात बदले नहीं हैं, उलट गए हैं। घर वही है, पिता वही हैं, मां वही है, बच्चे भी वही हैं, लेकिन रिश्तों का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया है। अब पिता कुछ कहना चाहें तो पहले सोचते हैं कि कहीं बच्चा बुरा न मान जाए, कहीं वह चुप होकर कमरे में न चला जाए, कहीं मोबाइल पर कोई उलटा-सीधा स्टेटस न डाल दे। मां प्यार से समझाती हैं तो जवाब आता है—मम्मी प्लीज़, माइंड योर ओन बिजनेस। यह बिजनेस कब रिश्तों में घुस गया, पता ही नहीं चला। पहले घर में बातें होती थीं, अब घर में रिएक्शन होते हैं। कभी 'पापा' शब्द में अपने आप सम्मान टपकता था। आवाज़ में झुकाव होता था, लहजे में दूरी और अपनापन दोनों। आज वही 'पापा' शब्द 'यार' के साथ चिपक गया है। पापा यार और इसी दो शब्दों में रिश्ता आधा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पिता नहीं, कोई सहयात्री हो जिससे बहस की जा रही हो। पहले पिता की डांट से बच्चे का भविष्य बनता था। आज बच्चे की अकड़ से रील बनती है और वही अकड़ तालियों में बदल जाती है। अगर पिता डांट दें तो कहा जाता है—बच्चे का आत्मसम्मान टूट जाएगा। लेकिन अगर बच्चा बदतमीजी करे तो जवाब मिलता है—अरे छोड़ो, जनरेशन गैप है। जैसे संस्कार पुराने सॉफ्टवेयर थे और अब उनका सपोर्ट खत्म हो गया हो।

हमने बच्चों को उड़ान देना सिखाया, इसमें कोई शक नहीं। हमने उन्हें खुलकर बोलना सिखाया, अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। यह सब ज़रूरी भी था। लेकिन इसी चक्कर में हमने उन्हें यह नहीं सिखाया कि उड़ान की दिशा भी होती है। हमने दोस्ती का पाठ पढ़ाया, लेकिन मर्यादा का पन्ना फाड़ दिया। हमने उन्हें सवाल करना सिखाया, लेकिन जवाब सुनने की आदत नहीं डाली। नतीजा यह हुआ कि हर बच्चा खुद को सही और सामने वाले को पुराना समझने लगा।

पहले स्कूल से मास्टर की शिकायत आती थी तो घर में कोई लंबी बहस नहीं होती थी। बाप बस इतना कह देता था—तू ही कुछ करके आया होगा। बच्चा चाहे सही हो या गलत, उसे यह एहसास मिल जाता था कि घर उसकी ढाल नहीं, उसका आईना है। आज वही शिकायत आती है तो सबसे पहले शिक्षक पर सवाल उठते हैं। पिता कहते हैं—टीचर का बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है। मां कहती हैं—मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। और बच्चा मन ही मन सीख जाता है कि गलती भी एक ऑप्शन है, क्योंकि उसके लिए एडवोकेट पहले से तैयार हैं।

कभी पिता की आंख उठती थी तो बच्चा अपने आप सीधा हो जाता था। आज पिता की आंख उठती है तो बच्चे की भौंहें चढ़ जाती हैं। पहले पिता पूछते थे—अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा? आज बच्चे कहते हैं—आप हमें समझते ही नहीं हो। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क सोच का है। पहले डर में भी अपनापन था, आज अपनापन जताने में भी एक दूरी है। पहले पिता के सामने चुप रहना संस्कार था, आज चुप रहना कमजोरी समझी जाती है।

हमने यह मान लिया कि दोस्ती ही हर रिश्ते का समाधान है। पिता दोस्त बन गए, मां सहेली बन गईं। यह सोच बुरी नहीं है, लेकिन अधूरी है। दोस्ती में भी सीमाएं होती हैं। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए। जिस घर में बाप हर कदम पूछकर रखे और छोरा मूंछ पर ताव दे, वहां सब कुछ चलता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से सब ढीला होता है। वहां चूल्हा जलता है, लेकिन रोटी कच्ची रह जाती है। पेट भर जाता है, लेकिन तमीज़ भूखी रह जाती है।

हम अक्सर कहते हैं कि आज के बच्चे बहुत समझदार हैं। सच यह है कि आज के बच्चे बहुत जल्दी समझदार बनने की मजबूरी में डाल दिए गए हैं। उन्हें फैसले लेने की आज़ादी तो दे दी गई, लेकिन फैसलों की जिम्मेदारी नहीं सिखाई गई। उन्हें अधिकारों की पूरी लिस्ट याद करा दी गई, लेकिन कर्तव्यों का अध्याय हटा दिया गया। हमने उन्हें राजा बना दिया और फिर हैरान होते हैं कि वे हुक्म क्यों चलाने लगे। जिस बच्चे ने कभी 'ना' नहीं सुनी, वह 'हां' की कीमत क्या जानेगा।

आज के दौर में हर समस्या का एक आसान जवाब ढूंढ़ लिया गया है—समय बदल गया है। हां, समय बदला है, लेकिन इंसान की बुनियादी ज़रूरतें नहीं बदलीं। आज भी बच्चे को सीमा चाहिए, आज भी उसे दिशा चाहिए, आज भी उसे यह एहसास चाहिए कि कोई है जो उससे बड़ा है, मजबूत है और सही-गलत का पैमाना है। फर्क बस इतना है कि अब सीमा को डर नहीं, समझ के साथ जोड़ना होगा। लेकिन समझ के नाम पर सब कुछ छोड़ देना भी समाधान नहीं है।

एक बुजुर्ग ने कभी हंसते हुए कहा था कि पहले के पिता फादर्स डे के मोहताज नहीं थे। उन्हें साल में एक दिन याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वे पिता हैं। आज फादर्स डे पर केक कटते हैं, फोटो खिंचती हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगती हैं, लेकिन साल के बाकी दिनों में पिता अक्सर खुद से ही बात करते हैं। पहले पिता का अधिकार था, आज पिता की भूमिका पर मीटिंग होती है।

अभियान

काली के सम्मुख खड़ा मनुष्य और भीतर टूटता भय

कालीघाट मंदिर तक पहुँचना किसी साधना-पथ की तरह शांत नहीं है। यह यात्रा किसी पहाड़ी चढ़ाई, वन-एकांत या मौन तपस्या जैसी नहीं लगती। यह यात्रा सीधे जीवन के बीचों-बीच से होकर गुजरती है। कोलकाता की तंग गलियाँ, लगातार बहता शोर, दुकानों की कतारें, फूलों की गंध, प्रसाद की पुकार, पंडों की ऊँची आवाज़ें—सब कुछ एक साथ चलता है। लगता है जैसे आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर नहीं, बल्कि जीवन के सबसे घने बाज़ार में प्रवेश कर रहे हों। और यही कालीघाट की पहली शिक्षा है। मां काली जीवन से अलग नहीं हैं। वे जीवन के केंद्र में हैं—उस जगह जहां व्यवस्था टूटती है, जहां भीड़ है, जहां असहजता है।

कालीघाट में प्रवेश करते ही मन किसी तैयारी का अवसर नहीं पाता। यहाँ कोई क्रम नहीं है, कोई लंबा ध्यान, कोई शांति का आमंत्रण नहीं। यहाँ सब कुछ अचानक घटता है। भीड़ आपको आगे धकेलती है, आवाज़ें कानों में टकराती हैं, और ठीक उसी क्षण जब आप संभलने की कोशिश करते हैं, काली की आँखें सीधे आपसे मिल जाती हैं। यह मिलन धीरे-धीरे नहीं होता। यह एक झटका है। जैसे किसी ने आपके भीतर जमी परत को एक झटके में हटा दिया हो।

काली का उग्र रूप अक्सर लोगों को भयभीत करता है। काली देह, बाहर निकली जीभ, मुंडमाला, रक्तिम स्वरूप—पहली दृष्टि में यह सब हिंसा और भय का प्रतीक लगता है। लेकिन कालीघाट में ठहरकर देखने वाला जानता है कि यह उग्रता डराने के लिए नहीं है। यह उग्रता ढोंग को तोड़ने के लिए है। काली वह सत्य हैं, जो सभ्यताओं को असहज करता है। वे हमें यह स्वीकार करने को बाध्य करती हैं कि भीतर हिंसा है, अहंकार है, पशुता है—और जब तक इसे देखा नहीं जाएगा, तब तक करुणा सिर्फ एक सुंदर शब्द बनी रहेगी।

पुराणों के अनुसार कालीघाट वही स्थान है जहाँ सती के दाएँ पैर की चार उँगलियाँ गिरी थीं। यही कारण है कि यहाँ देवी की पूर्ण मूर्ति नहीं, बल्कि पवित्र पदचिह्न की पूजा होती है। यह तथ्य साधारण नहीं है। यह मंदिर पूर्णता का उत्सव नहीं है। यह मंदिर अपूर्णता की स्वीकृति है। यहाँ शक्ति संपूर्ण मूर्ति में नहीं, बल्कि टूटे हुए अवशेष में वास करती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो टूटा है, जो अधूरा है, वही अक्सर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। कालीघाट में देवी की जीभ बाहर निकली हुई दिखाई देती है। सामान्य दृष्टि इसे क्रोध का प्रतीक मान लेती है। लेकिन कथा बताती है कि यह क्रोध नहीं, आत्मबोध है। जब देवी ने अहंकारवश शिव को अपने चरणों तले दबा लिया, तब जैसे ही उन्हें इसका बोध हुआ, लज्जा और आत्मग्लानि में उनकी जीभ बाहर आ गई। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि सबसे उग्र शक्ति भी आत्मचेतना के सामने झुक जाती है। काली यहाँ अहंकार का उत्सव नहीं हैं, बल्कि अहंकार के टूटने का दृश्य हैं।

कालीघाट उन गिने-चुने शक्तिपीठों में है जहाँ पशु-बलि की परंपरा की स्मृति आज भी जीवित है। आधुनिक मन इसे असहजता से देखता है। यह असहजता स्वाभाविक है, क्योंकि आधुनिक समाज प्रतीकों को समझने में कमजोर हो गया है। कालीघाट में बलि उत्सव नहीं है। यह जिम्मेदारी है। यह याद दिलाने की प्रक्रिया है कि शक्ति मुफ्त में नहीं मिलती। कुछ छोड़ना पड़ता है। आज बलि अधिकतर प्रतीकात्मक है, लेकिन उसका संदेश वही है—अपने भीतर के पशु-स्वभाव, हिंसा और लोभ की बलि।

कालीघाट को रामकृष्ण परमहंस के बिना समझना अधूरा है। उनके लिए काली कोई डरावनी देवी नहीं थीं। वे उनके लिए जीवित माँ थीं—करुणामयी, वात्सल्य से भरी, संवाद करने वाली। रामकृष्ण ने काली को तंत्र की भयावहता से निकालकर प्रेम और भक्ति के केंद्र में रखा। उन्होंने दिखाया कि उग्रता और करुणा विरोधी नहीं हैं। उग्रता करुणा की रक्षा करती है। जिस करुणा में उग्रता नहीं होती, वह अक्सर कमजोर हो जाती है।

कालीघाट का एक कठोर सत्य यह भी है कि यहाँ धर्म और यथार्थ अलग-अलग नहीं हैं। यहाँ पंडा-प्रथा है, दान-दक्षिणा है, शीघ्र दर्शन की व्यवस्था है। कई श्रद्धालु इससे असहज होते हैं। लेकिन कालीघाट किसी आदर्श लोक का निर्माण नहीं करता। यह जीवन का प्रतिबिंब है। यहाँ आस्था और स्वार्थ साथ-साथ चलते हैं। यहाँ करुणा भी है और लेन-देन भी। काली यहाँ किसी को प्रमाणपत्र नहीं देतीं। वे यह नहीं पूछतीं कि कौन कितना शुद्ध है। वे सबको स्वीकार करती हैं—जैसा है, वैसा।

यह मंदिर हमें स्त्री-शक्ति के एक कठिन सत्य से परिचित कराता है। स्त्री-शक्ति को कोमल, सुंदर और सौम्य बनाकर पूजना आसान है। लेकिन उसे उग्र, नग्न, रक्तिम और असहज रूप में स्वीकार करना साहस माँगता है। कालीघाट उसी साहस की परीक्षा लेता है। यहाँ शक्ति किसी रहस्यमयी गुफा में नहीं छिपी है। वह सड़क पर है, भीड़ में है, शोर में है। वह उस जगह है जहाँ जीवन सबसे असुविधाजनक होता है।

कालीघाट में दर्शन कुछ ही क्षणों का होता है। आपको रुकने नहीं दिया जाता। कोई लंबा ध्यान नहीं, कोई भावुक ठहराव नहीं। लेकिन वही क्षण इतना तीव्र होता है कि भीतर कुछ टूट जाता है। काली की आँखें स्थिर नहीं लगतीं। ऐसा लगता है जैसे वे हर व्यक्ति को अलग-अलग देख रही हों। कोई रो पड़ता है, कोई डर जाता है, कोई भीतर से खाली हो जाता है, कोई अचानक शांत हो जाता है। यह अनुभव सामूहिक नहीं, पूरी तरह व्यक्तिगत होता है।

आज कालीघाट एक पर्यटन स्थल भी है, एक राजनीतिक उपस्थिति भी है। व्यवस्थाएँ सुधर रही हैं, सुविधाएँ बढ़ रही हैं। लेकिन मंदिर की आत्मा अब भी वही है—कच्ची, तीखी और असुविधाजनक। यह मंदिर सजावटी अध्यात्म को नकारता है। यह आपको अच्छा महसूस कराने का वादा नहीं करता। यह आपको सच दिखाने का साहस करता है।

कालीघाट हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सुंदर होना आवश्यक नहीं। आस्था का आरामदेह होना भी अनिवार्य नहीं। देवी का मुस्कुराना जरूरी नहीं। कभी-कभी करुणा सबसे उग्र रूप में प्रकट होती है—ताकि वह हमें जगा सके। काली हमें डराती नहीं हैं। वे हमें हमारे डर से मिलवाती हैं।

कालीघाट से लौटते समय व्यक्ति वही नहीं रहता जो वह आया था। कुछ भीतर गिर चुका होता है—शायद अहंकार, शायद भ्रम, शायद सुरक्षा का नकली कवच। और उसी टूटन के बीच कहीं करुणा जन्म लेती है। यह करुणा मुलायम नहीं होती, यह सच्ची होती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सोने-चांदी की बेकाबू कीमतें बन गईं बेटियों की शादी पर संकट
राज्यसभा में नीरज डांगी ने सरकार पर किया तीखा हमला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किए जाने के मौके पर सांसद नीरज डांगी ने सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सोने और चांदी की कीमतें अब पूरी तरह बेकाबू हो गई हैं और इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण भारत पर पड़ा है, जहां बेटियों के विवाह के लिए परिवारों की कमर टूट चुकी है।
नीरज डांगी ने सदन में कहा कि पिछले 13 महीनों में चांदी की कीमतों में 306 प्रतिशत और सोने की कीमतों में 111 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस देश में सोना-चांदी महिलाओं की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हो, वहां इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर आर्थिक विफलता को दर्शाता है। उनका कहना था कि किसान, मजदूर और निम्न-मध्यम वर्ग के लोग अपनी बेटियों के विवाह के लिए अब न्यूनतम आभूषण तक नहीं खरीद पा रहे हैं।
नीरज डांगी ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें जरूर करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारी जीएसटी, उच्च आयात शुल्क और जमाखोरों पर नियंत्रण न रखने की नीति ने महिलाओं की बचत को मूल्यहीन बना दिया है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर महिलाओं पर आर्थिक दबाव बताते हुए कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाएं इस बेकाबू महंगाई की मार झेल रही हैं और केवल जमाखोरों को संरक्षण मिल रहा है।
सांसद ने यह भी चेतावनी दी कि बढ़ती कीमतों का असर केवल आम परिवारों तक ही नहीं बल्कि छोटे सुनार और व्यवसायियों पर भी पड़ा है। रोजगार संकट बढ़ रहा है और छोटे कारोबारी अपने व्यापार को संभालने में असमर्थ हो रहे हैं। नीरज डांगी ने सरकार से मांग की कि सोने और चांदी की कीमतों पर हस्तक्षेप किया जाए, जीएसटी की दरों में कटौती की जाए और जमाखोरों पर कठोर कदम उठाए जाएं।

सत्र में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नेशनल करियर सर्विस को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि सबसे बड़ा रोजगारदाता अभी भी भारत सरकार और उसके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इनके खाली पदों और भर्ती की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया। सुरजेवाला ने इस तथ्य पर चिंता जताते हुए कहा कि सदन में कई बार सवाल पूछने के बावजूद सरकार ने अभी तक इन आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया है।
विश्लेषकों का मानना है कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें न केवल पारिवारिक बजट पर दबाव डाल रही हैं, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी बढ़ा रही हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में विवाह और अन्य पारंपरिक आयोजनों के लिए यह संकट गंभीर रूप ले चुका है। इससे परिवारों में तनाव बढ़ा है और महिलाएं अपने आभूषणों और आर्थिक सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे रुझान और घरेलू वित्तीय नीतियों में उचित नियंत्रण की कमी है। आयात शुल्क और जीएसटी दरों की उच्चता ने घरेलू बाजार पर सीधे असर डाला है, जिससे आम नागरिकों के लिए सोने और चांदी खरीदना मुश्किल हो गया है।
राज्यसभा में उठाए गए इस मुद्दे पर कई सांसदों ने चिंता जताई और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि यदि कीमतों पर नियंत्रण और उचित नीति न बनाई गई तो ग्रामीण भारत में विवाह और पारिवारिक आयोजनों के पारंपरिक स्वरूप पर गंभीर असर पड़ेगा। इससे परिवारों की वित्तीय योजना और महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है।
नीरज डांगी और सुरजेवाला ने संयुक्त रूप से सरकार से अपील की कि न केवल सोने-चांदी की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए, बल्कि रोजगार और सार्वजनिक क्षेत्र में खाली पदों की जानकारी भी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना था कि पारदर्शिता और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सोने और चांदी के बढ़ते दामों से प्रभावित छोटे सुनार और व्यवसायियों की वित्तीय स्थिति पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने सरकार से सुझाव दिया कि जमाखोरों और एग्रीगेटर्स पर कड़ी नजर रखी जाए और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों को राहत मिल सके।
राज्यसभा में उठाए गए इस मुद्दे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सोना-चांदी की कीमतों की बढ़ोतरी केवल निवेशकों या बड़े व्यापारियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे आम परिवारों, बेटियों के विवाह और महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सामाजिक और आर्थिक संकट बन गया है।
संसद में उठाए गए सवाल और सांसदों के तीखे तेवर ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए और घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए रणनीतिक उपाय लागू करे। साथ ही, रोजगार और सार्वजनिक आंकड़ों की पारदर्शिता सुनिश्चित करके आम नागरिकों का भरोसा बढ़ाया जाए।
इस पूरे मुद्दे से यह भी संकेत मिलता है कि आगामी बजट और नीतिगत घोषणाओं में सोना-चांदी की कीमतों पर नियंत्रण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े आर्थिक उपायों को प्रमुखता से शामिल करना अनिवार्य हो गया है। सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह तेजी से नीति बनाए और घरेलू बाजार को संतुलित करते हुए आम नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करे।

अयोध्या जेल से दो बंदी फरार, सुरक्षा में सेंध से मचा हड़कंप, जेल अधीक्षक समेत पांच सस्पेंड

(जीएनएस)। अयोध्या। जनपद की जिला कारागार व्यवस्था गुरुवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक के कारण सुर्खियों में आ गई, जब दो विचाराधीन बंदी जेल परिसर से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन और पुलिस में अफरा-तफरी मच गई, और फरार बंदियों की धरपकड़ के लिए पूरे जिले में विशेष अभियान शुरू किया गया।
सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर तत्काल जिला जेल पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बंदियों को तन्हाई बैरक में रखा गया था। बंदियों ने बैरक की संरचना को क्षतिग्रस्त कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और इसके बाद जेल की बाउंड्री वॉल को फांदकर फरार हो गए।

जेल से फरार बंदियों की पहचान गोलू अग्रहरी उर्फ सूरज अग्रहरी निवासी अमेठी और शेर अली निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, गोलू अग्रहरी हत्या के प्रयास के मामले में और शेर अली दुष्कर्म के आरोप में जेल में निरुद्ध था। दोनों बंदियों की फरारी ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फरार बंदियों की तलाश के लिए पुलिस ने जिले में व्यापक अभियान चलाया। कई टीमों को संभावित ठिकानों पर दबिश देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन समीक्षा की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि फरार बंदियों की कोई भी मदद करने वाले या सुरक्षा व्यवस्था में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस गंभीर सुरक्षा चूक के चलते डीजी जेल पीसी मीणा ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, जेलर जेके यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी समेत एक हेड जेल वॉर्डन और तीन अन्य वार्डनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और सुरक्षा की गंभीर लापरवाही के कारण की गई है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने स्पष्ट किया कि जेल प्रशासन की किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि फरार बंदियों की शीघ्र गिरफ्तारी और जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

उत्तराखंड को Wings India 2026 में 'बेस्ट स्टेट फॉर एविएशन इकोसिस्टम' का सम्मान पर्यटन, आपदा प्रबंधन और हवाई कनेक्टिविटी में राज्य की उपलब्धि का प्रमाण

(जीएनएस)। नई दिल्ली। उत्तराखंड को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी Wings India 2026 में "Best State for Promotion of Aviation Ecosystem" का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान राज्य सरकार द्वारा विमानन इकोसिस्टम के सुदृढ़ीकरण, नीति समर्थन और प्रभावी प्रशासनिक प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के सचिव समीर कुमार सिन्हा द्वारा उत्तराखंड प्रतिनिधिमंडल को प्रदान किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के सचिव सचिन कुर्वे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सिंह टोलिया और हेड ऑफ ऑपरेशंस कैप्टन अमित शर्मा उपस्थित रहे। राज्य के अधिकारियों ने समारोह में बताया कि यह सम्मान उत्तराखंड की समग्र विमानन नीति, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य के पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का यह प्रयास पर्यटन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार लेकर आया है। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में किए गए कदम न केवल प्रभावी रहे हैं, बल्कि राज्य को एक उभरता विमानन हब बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार, उड़ान योजना के सफल क्रियान्वयन और आधुनिक विमानन अवसंरचना के विकास से अब राज्य तेजी से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान बना रहा है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला है बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी सुगम हुई है।"
उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में हवाई अड्डों और हेलिपोर्ट नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, श्रीनगर, गढ़वाल और उत्तरकाशी क्षेत्रों में नियमित हवाई सेवाओं की सुविधा शामिल है। UCADA के अधिकारियों के अनुसार, इन पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और पर्यटन विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड का यह सम्मान राज्य की समग्र नीति, विमानन अवसंरचना और प्रशासनिक दक्षता का वैश्विक स्तर पर मूल्यांकन है। Wings India 2026 जैसी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर राज्य का चयन यह दर्शाता है कि उत्तराखंड न केवल भारत के भीतर बल्कि विमानन और पर्यटन के वैश्विक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य प्रदेश को ऐसे हवाई संपर्क और आधुनिक विमानन ढांचे से जोड़ना है, जिससे हर नागरिक को सुरक्षित, समय पर और विश्वसनीय हवाई सेवाओं की सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट एयरपोर्ट और उड़ान मार्गों के विस्तार के माध्यम से हवाई यात्रा को और भी सुलभ और प्रभावी बनाएगी।

वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की आर्थिक रफ्तार कायम, प्रवीण खंडेलवाल ने सर्वेक्षण को बताया भरोसेमंद मार्गदर्शक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी, महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों के बीच भी अपनी मजबूती बनाए रखी है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भारतीय संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण न केवल आर्थिक आंकड़ों का संकलन है, बल्कि यह देश की विकास यात्रा की दिशा और नीतिगत स्पष्टता का भी प्रमाण है।
खंडेलवाल ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित 6.8 से 7.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर इस बात का संकेत है कि भारत की आर्थिक नींव मजबूत है। उन्होंने बताया कि जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई, ब्याज दरों की अनिश्चितता, ऊर्जा संकट और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से जूझ रही हैं, ऐसे समय में भारत की निरंतर आर्थिक गति उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में पेश आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर अब भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।
प्रवीण खंडेलवाल ने निवेशकों और आम नागरिकों के बीच बढ़ते भरोसे को आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाए गए संरचनात्मक सुधार, बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन, एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने और कारोबार को आसान बनाने की पहलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन नीतिगत कदमों से व्यापारियों, उद्योगपतियों और निवेशकों के मन में देश के आर्थिक भविष्य को लेकर विश्वास पैदा हुआ है।
खंडेलवाल ने आर्थिक सर्वेक्षण को आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि इससे व्यापार, निवेश और रोजमर्रा के नागरिकों के जीवन में स्थिरता आएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सर्वेक्षण भारत की सतत विकास यात्रा का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।
उन्होंने वैश्विक आर्थिक माहौल की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि महंगाई, विदेशी निवेश में उतार-चढ़ाव, तेल और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं ने कई देशों की आर्थिक प्रगति को प्रभावित किया है, लेकिन भारत ने इन सभी चुनौतियों के बावजूद अपने विकास की रफ्तार बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता नीति-निर्माताओं की दूरदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।
प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की सशक्तिकरण नीति, निर्यात संवर्धन और डिजिटल इंडिया पहल ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों में स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करके सरकार ने रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है, जिससे आर्थिक वृद्धि में स्थायित्व बना है।
इसके अलावा, खंडेलवाल ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने निवेशकों के लिए आश्वासन देने का काम किया है। वैश्विक निवेशक अब भारत में निवेश करने को सुरक्षित और लाभप्रद मानते हैं, क्योंकि देश की आर्थिक नीतियां पारदर्शी, दीर्घकालिक और विकासोन्मुखी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह भरोसा भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर और सशक्त बनाने में मदद करेगा।
खंडेलवाल ने कहा कि आगामी बजट में ध्यान कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर विकास के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट में रोजगार सृजन, निवेश को प्रोत्साहन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने वाले उपाय शामिल होंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी।
अंत में खंडेलवाल ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 यह प्रमाणित करता है कि भारत की आर्थिक नीति विश्वसनीय, दीर्घकालिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की विकास यात्रा में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी आर्थिक निर्णय जिम्मेदारी, पारदर्शिता और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ लिए जा रहे हैं। उन्होंने निवेशकों, व्यापारियों और आम नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे इस विकास यात्रा का हिस्सा बनें और मिलकर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करें।
भारत की आर्थिक मजबूती, नीति की स्पष्टता और निवेशकों के विश्वास ने इस सर्वेक्षण के माध्यम से यह संदेश दिया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की रफ्तार कायम है और आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर एक सशक्त और स्थिर शक्ति के रूप में उभरेगा।

भारत के डिजाइन कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, DPIIT ने जारी किया संशोधित प्रस्ताव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने अपने डिजाइन संरक्षण ढांचे को वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने डिज़ाइन एक्ट, 2000 में व्यापक संशोधन के लिए एक अवधारणा पत्र सार्वजनिक किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के डिजाइन उद्योग को नई दिशा देना, डिजिटल और वर्चुअल डिज़ाइनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के साथ भारतीय डिजाइन प्रणाली को समन्वयित करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन भारत को रियाद डिज़ाइन लॉ संधि और हेग समझौते के तहत औद्योगिक डिज़ाइनों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के साथ पूरी तरह तालमेल में लाने का प्रयास है। मंत्रालय का मानना है कि इससे भारत का डिज़ाइन इकोसिस्टम मजबूत होगा और 'डिज़ाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड' की परिकल्पना को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि डिज़ाइन उद्योग में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव जरूरी है। अवधारणा पत्र में डिज़ाइन कानून की कई महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव का सुझाव दिया गया है। इसमें डिज़ाइन और आर्टिकल की परिभाषा में संशोधन करके डिजिटल और वर्चुअल डिज़ाइनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही 12 महीने की ग्रेस पीरियड व्यवस्था लागू करने का सुझाव है, जिससे आवेदकों को उनके डिज़ाइन को सार्वजनिक करने के बाद भी सुरक्षित रखने का समय मिलेगा। इसके अलावा, डिज़ाइन के प्रकाशन को 30 महीने तक टालने का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि नवाचारक अपनी रणनीति के अनुसार निर्णय ले सकें।
अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप समय-सीमा में राहत देने और वैधानिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसके तहत यदि किसी डिज़ाइन का उल्लंघन होता है तो डिज़ाइन होल्डर को उचित कानूनी संरक्षण और मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, डिज़ाइन संरक्षण की अवधि में संशोधन करने और एक ही आवेदन में कई डिज़ाइनों को दर्ज करने की सुविधा देने का सुझाव भी दिया गया है। इससे डिज़ाइन प्रक्रिया सरल और व्यावहारिक होगी, जो उद्योग और नवप्रवर्तनक दोनों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। अवधारणा पत्र में डिज़ाइन आवेदन की श्रेणीकरण प्रणाली को अधिक लचीला बनाने और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप प्रक्रियात्मक सुधारों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य डिज़ाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। DPIIT का मानना है कि इन बदलावों से भारत में डिजाइन पेशेवरों, स्टार्टअप और बड़ी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे।
DPIIT ने इन संशोधन प्रस्तावों पर उद्योग जगत, डिजाइन पेशेवरों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। विभाग ने कहा है कि प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगे की चर्चा और अंतिम संशोधनों को तैयार किया जाएगा। अवधारणा पत्र सार्वजनिक परामर्श के लिए DPIIT की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, ताकि सभी इच्छुक पक्ष अपनी राय साझा कर सकें।

सोना वायदा में 9085 रुपये, चांदी वायदा में 19634 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 162 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 395568.09 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 148591.77 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 246952.95 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 50501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5429.15 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 127819.35 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 169882 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 180779 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 169882 रुपये पर पहुंचकर, 165915 रुपये के पिछले बंद के सामने 9085 रुपये या 5.48 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 175000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 10774 रुपये या 7.7 फीसदी बढ़कर 150750 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 1326 रुपये या 7.55 फीसदी बढ़कर 18881 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी फरवरी वायदा 168000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 182130 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 168000 रुपये पर पहुंचकर, 9110 रुपये या 5.45 फीसदी बढ़कर 176202 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 175500 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 190018 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 175500 रुपये पर पहुंचकर, 174329 रुपये के पिछले बंद के सामने 13872 रुपये या 7.96 फीसदी बढ़कर 188201 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 399000 रुपये के भाव पर खूलकर, 409800 रुपये के ऑल टाइम हाई और 395001 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 385366 रुपये के पिछले बंद के सामने 19634 रुपये या 5.09 फीसदी की तेजी के संग 405000 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 23961 रुपये या 6.12 फीसदी की तेजी के संग 415697 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 23901 रुपये या 6.1 फीसदी की मजबूती के साथ 415702 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कमोडिटी वायदाओं में 148591.77 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 246952.95 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 127819.35 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 50501 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 15692.24 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 98.1 रुपये या 7.42 फीसदी की तेजी के संग 1419.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 12.5 रुपये या 3.74 फीसदी की तेजी के संग 346.9 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 15.4 रुपये या 4.65 फीसदी की मजबूती के साथ 346.85 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 4.3 रुपये या 2.19 फीसदी बढ़कर 200.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।
इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4518.68 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5894 रुपये के भाव पर खूलकर, 6005 रुपये के दिन के उच्च और 5887 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 162 रुपये या 2.79 फीसदी की मजबूती के साथ 5964 रुपये प्रति बैरल बोला गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 163 रुपये या 2.81 फीसदी बढ़कर 5965 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 351 रुपये के भाव पर खूलकर, 363.3 रुपये के दिन के उच्च और 348 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 342.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 10 रुपये या 2.92 फीसदी की तेजी के संग 352.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 10 रुपये या 2.92 फीसदी की तेजी के संग 353 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।
कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 1008.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.9 रुपये या 0.49 फीसदी की गिरावट के साथ 987.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।
कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 90964.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 36854.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 13318.98 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 1092.42 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 160.70 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 1092.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1186.43 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3323.36 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.94 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।
ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 18749 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 111452 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 34154 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 511505 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63880 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14069 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 35283 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99225 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 23278 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 18804 लोट के स्तर पर था।
इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 49024 पॉइंट पर खूलकर, 51880 के उच्च और 49024 के नीचले स्तर को छूकर, 2904 पॉइंट बढ़कर 50501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।
कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 93.8 रुपये की बढ़त के साथ 305.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.4 रुपये की बढ़त के साथ 40.95 रुपये हुआ।
सोना फरवरी 172000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 10597 रुपये की बढ़त के साथ 20931.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 365000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 12541 रुपये की बढ़त के साथ 63491 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1390 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 68.29 रुपये की बढ़त के साथ 91.51 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 345 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.13 रुपये की बढ़त के साथ 6.49 रुपये हुआ।
पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 76.2 रुपये की गिरावट के साथ 268.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.55 रुपये की गिरावट के साथ 36.95 रुपये हुआ।
सोना फरवरी 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1398.5 रुपये की गिरावट के साथ 3213.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 800.5 रुपये की गिरावट के साथ 6450 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 12.29 रुपये की गिरावट के साथ 21.24 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 285 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 14 पैसे के सुधार के साथ 0.49 रुपये हुआ।

गुजरात से गिरफ्तार आतंकी फैजान से पूछताछ के लिए यूपी ATS अहमदाबाद पहुंची, रामपुर नेटवर्क की पड़ताल तेज

(जीएनएस)। लखनऊ। गुजरात के नवसारी से संदिग्ध आतंकी फैजान की गिरफ्तारी ने उत्तर प्रदेश सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। नवसारी पुलिस और एटीएस ने फैजान को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें एक पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है और स्थानीय जांच एजेंसियों के अनुसार उसकी आतंकवादी गतिविधियां राज्य के कई हिस्सों से जुड़ी हो सकती हैं। इस गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की एक विशेष टीम अहमदाबाद रवाना हुई ताकि फैजान से गहन पूछताछ की जा सके और उसके नेटवर्क की पूरी परतों का पता लगाया जा सके।

जांच में सामने आया है कि फैजान पिछले छह से सात महीनों से आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया कि उसने हथियार उत्तर प्रदेश में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किए थे और उनका उद्देश्य टारगेटेड हत्याओं और दहशत फैलाने के लिए था। फैजान ने यह भी बताया कि वह अबू बकर नामक व्यक्ति के संपर्क में था और करीब तीन महीने पहले एक संदिग्ध आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद उसकी गतिविधियों की तीव्रता बढ़ी और उसने अपने आतंकवादी नेटवर्क का विस्तार करना शुरू कर दिया।

फैजान के मोबाइल फोन की जांच से कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज, चैट और वीडियो प्राप्त हुए हैं। इनमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े प्रचार वीडियो, भड़काऊ भाषण और कुछ कुख्यात आतंकियों के वीडियो शामिल हैं। इसके अलावा मोबाइल में देश विरोधी तस्वीरें और अन्य संवेदनशील दस्तावेज भी मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दस्तावेजों और डिजिटल सुरागों के माध्यम से फैजान के पूरे नेटवर्क और उसकी योजनाओं की पड़ताल की जा सकती है।

यूपी एटीएस के वरिष्ठ अधिकारीयों ने बताया कि रामपुर जिले में फैजान के संभावित सहयोगियों और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आरोपी के संपर्क और सहयोगियों की पहचान करने के लिए कई टीमों को अलग-

अलग जिम्मेदारी दी गई है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिल रहे हैं कि फैजान के नेटवर्क में स्थानीय लोग भी शामिल हैं, जो उसके आतंकवादी मिशन को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। इसके अलावा एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके संपर्क देश के अन्य हिस्सों तक भी फैले हुए हैं या नहीं।

जांच एजेंसियों के अनुसार, फैजान की गिरफ्तारी ने एक बड़े संभावित आतंकवादी खतरे को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को हल्के में नहीं ले रही हैं और फैजान से पूछताछ को और तेज कर दी गई है। इससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में आतंकवादी नेटवर्क के तार और योजनाएं सामने आने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों के अनुसार, फैजान जैसी गिरफ्तारी यह दर्शाती है कि आतंकवादी संगठन अपने ठिकानों और सहयोगियों के माध्यम से देश में सक्रिय हैं। उनका उद्देश्य आम नागरिकों में डर और आतंक फैलाना होता है। यूपी एटीएस और गुजरात एटीएस की संयुक्त कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे खतरे समय रहते निष्प्रभावी किए जाएं। एजेंसियों का मानना है कि फैजान के पूछताछ से आतंकवादियों के नेटवर्क के कई अहम सुराग मिल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल भविष्य में संभावित हमलों को रोकने के लिए किया जाएगा। जांच में यह बात भी सामने आई है कि फैजान ने हथियारों के अलावा डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग कर आतंक फैलाने की योजना बनाई थी। इसके लिए वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भड़काऊ सामग्री और आतंकवादी संदेश फैलाता था। एजेंसियों ने इस बात को गंभीरता से लिया है और डिजिटल सुरागों की जांच भी तेजी से कर रही हैं। इसके साथ ही आरोपी के नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सतर्कता बरती जा रही है।

यूपी एटीएस के वरिष्ठ अधिकारीयों ने कहा कि पूछताछ के दौरान फैजान के सहयोगियों और उनके संभावित ठिकानों की पहचान करना प्राथमिकता में है। रामपुर जिले और आसपास के इलाकों में छापेमारी जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क को समय रहते निष्प्रभावी करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जांच टीम का मानना है कि फैजान के संपर्कों और नेटवर्क की गहन पड़ताल से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी कहना है कि इस गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी संगठन भारत में सक्रिय हैं और उनके पास हथियार, प्रशिक्षित लोग और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने की क्षमता है। ऐसे में समय रहते उनकी योजनाओं को विफल करना आवश्यक है। यूपी एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियां पूरे देश में सतर्क हैं और संभावित आतंकवादी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी जा रही है।

फैजान के खिलाफ आगे की पूछताछ में यह भी पता लगाया जाएगा कि उसके नेटवर्क में कौन-कौन से लोग शामिल हैं, उसके संपर्क किस तरह के थे और किस प्रकार के हथियार और संसाधन जुटाए गए। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि उसके नेटवर्क का असर केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था या अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। एजेंसी इस मामले में उच्च स्तरीय समन्वय और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है।

जांच एजेंसियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस या एटीएस को दें। अधिकारियों का मानना है कि आम लोगों की सतर्कता और जानकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान देती है।

इस गिरफ्तारी और गहन जांच से यह संदेश गया है कि भारत में सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ सतर्क हैं और किसी भी तरह के खतरे को समय रहते नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। यूपी एटीएस की अहमदाबाद में फैजान से गहन पूछताछ और रामपुर नेटवर्क की पड़ताल अगले कुछ दिनों में इस मामले के सभी पहलुओं को उजागर करेगी और संभावित आतंकवादी खतरों को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

गुरुग्राम के पांच सितारा होटल में IT इंजीनियर की संदिग्ध मौत: हार्ट अटैक या हत्या, पुलिस गहन जांच में जुटी

(जीएनएस)। गुरुग्राम। सेक्टर-29 स्थित पाँच सितारा होटल क्राउन प्लाजा में एक IT इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने शहर और कारोबारी समुदाय में चिंता और सनसनी फैला दी है। मृतक इंजीनियर बेंगलुरु से अपने कार्यालय के काम के सिलसिले में गुरुग्राम आया हुआ था और वह होटल में विदेशी कर्मचारियों के साथ ठहरा हुआ था। गुरुवार सुबह होटल स्टाफ ने बाथरूम में मृतक का शव देखा और इसकी तुरंत जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।

पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट या हिंसक निशान नहीं पाए गए हैं। इस आधार पर प्रारंभिक अनुमान लगाया गया कि मृतक की मौत हार्ट अटैक या स्वास्थ्य संबंधी किसी अचानक समस्या के कारण हुई होगी। हालांकि, पुलिस ने इस संभावना से इंकार नहीं किया कि किसी साजिश या अपराध के तहत भी यह घटना हुई हो सकती है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम और होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही मौत के असली कारण का पता चलेगा।

होटल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे पुलिस को प्रवेश में थोड़ी कठिनाई हुई। मास्टर चाबी की मदद से कमरे का दरवाजा खोला गया। होटल में ठहरने और कमरे की बुकिंग कंपनी द्वारा कराए जाने की पुष्टि भी पुलिस ने की है। इसके साथ ही होटल स्टाफ और साथ ठहरे अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि यह स्वाभाविक मृत्यु है या हत्या की साजिश के तहत की गई है। गुरुग्राम पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। स्थानीय लोग और होटल स्टाफ इस घटना से स्तब्ध हैं। होटल के आसपास सुरक्षा और निगरानी के सवाल भी उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि होटल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच के साथ ही होटल में तैनात कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन समीक्षा की जाएगी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार बड़े होटल और व्यावसायिक ठिकानों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को और मजबूत बनाने की जरूरत है। घटना ने यह भी साबित किया कि जब कर्मचारी और ग्राहकों की सुरक्षा सीधे जुड़े मामलों में सावधानी नहीं बरती जाती, तो सामान्य दिनचर्या भी भय और तनाव का कारण बन सकती है।

होटल प्रबंधन ने घटना के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया और मामले में सहयोग देने की बात कही। वहीं, मृतक के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है और वे गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस परिवार से भी पूछताछ कर मृतक के स्वास्थ्य इतिहास और हाल की गतिविधियों का विवरण जुटा रही है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी—चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी कारण हो, होटल की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो या कोई अपराधी गतिविधि। मामले की गहनता और गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले को अदालत तक ले जाया जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल गुरुग्राम में बड़े होटलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत को उजागर किया है, बल्कि व्यवसायिक यात्रियों और कर्मचारियों के लिए सतर्क रहने का संदेश भी दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और होटल के सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने का कड़ा आदेश दिया

(जीएनएस)। कोलकाता। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती अवैध घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी की घटनाओं के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि सीमा पर सुरक्षा और फेंसिंग के लिए खरीदी गई सभी जमीन 31 मार्च, 2026 तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को सौंप दी जाए। यह आदेश चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने सुनाया।

मामला लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों के घेरे में रहा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लगातार आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा उपायों में देरी कर रही है, जिससे सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। भाजपा की ओर से दायर की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल में सीमा पर खरीदी गई जमीन को BSF को सौंपने में देरी की जा रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के सुरक्षा तंत्र में कमजोरी आ रही है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव, राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक देरी को सुरक्षा उपायों में बाधा डालने का औचित्य नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि सीमा की सुरक्षा राजनीति या अहंकार से प्रभावित नहीं होती, और हर क्षण की देरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि समय पर कार्रवाई न होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

याचिका में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल की भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा (IBB) लगभग 2,216.70 किलोमीटर लंबी है और राज्य के नौ जिलों में फैली हुई है। बिना बाड़ वाली इस सीमा पर अवैध गतिविधियों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। PIL में विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को गंभीर खतरे के रूप में उजागर किया गया।

राज्यसभा में पूछे गए सवालों के डेटा को कोर्ट के सामने रखा गया। आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में सीमा पार घुसपैठ के प्रयासों में तेज़ी देखी गई है, जिसमें 2023, 2024 और जुलाई 2025 तक की घटनाओं में विशेष वृद्धि हुई। अदालत ने इन सब तथ्यों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सुरक्षा उपायों में देरी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। अधिकारियों के अनुसार, BSF को जमीन सौंपने के बाद सीमा पर फेंसिंग, चौकसी और निगरानी के आधुनिक उपाय लागू किए जाएंगे, ताकि अवैध गतिविधियों को रोकने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों और सीमा पार व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कदम भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और बंगाल में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार और BSF के बीच जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज़ गति से पूरी की जाएगी। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा फेंसिंग और आधुनिक निगरानी तंत्र से अवैध घुसपैठ, तस्करी और अपराधों में कमी आने की उम्मीद है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि यह आदेश राज्य सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को न केवल हल करेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार भी लाएगा। इस आदेश के पालन में देरी नहीं हो सकती, और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता के रूप में माना गया है। 31 मार्च 2026 तक BSF को जमीन सौंपने का लक्ष्य तय होने के बाद, अब राज्य सरकार की जवाबदेही स्पष्ट हो गई है। इस कदम से भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और निगरानी को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और सीमावर्ती जिलों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा: इल्तिजा मुफ्ती ने उत्तराखंड मारपीट मामले पर सरकार को घेरा

(जीएनएस)। देहरादून। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र से हाल ही में सामने आए कश्मीरी युवक पर हमले के मामले ने पूरे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक सहिष्णुता को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। बुधवार, 28 जनवरी को 18 साल के कश्मीरी शॉल बेचने वाले युवक के साथ लोहे की रॉड से बेरहमी से मारपीट की गई। इस घटना में उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत के कारण देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया।

युवक ने पुलिस को बताया कि हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी पहचान पूछने के बाद यह शुरू हुआ। जब उसने बताया कि वह कश्मीर का रहने वाला है और मुस्लिम समुदाय से है, तभी लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस बर्बरता ने न केवल पीड़ित परिवार को हताश किया, बल्कि पूरे देश में कश्मीरियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता भी बढ़ा दी है।

इस घटना पर कांग्रेस नेता इल्तिजा महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार को कड़ा शब्दों में घेरा। उन्होंने कहा कि यह केवल कुछ व्यक्तिगत अपराधियों की हिंसा नहीं है, बल्कि संपूर्ण संस्थागत छूट के कारण अपराधियों को विश्वास है कि वे बिना किसी रोक-टोक के कश्मीरी युवाओं पर हमला कर सकते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सक्रिय रूप से ऐसे 'कुछ लोगों' को मुख्यधारा में ला रही है, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कमजोर पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलने की आशंका बढ़ जाएगी।

उत्तराखंड पुलिस ने इस घटना के संबंध में तुरंत जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और हर संभव मदद का

आश्वासन दिया है। पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित सुरागों की जांच की जा रही है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। उन्होंने बताया कि यदि समाज में अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता और सुरक्षा की भावना मजबूत नहीं की गई तो भविष्य में ऐसे मामले बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कानूनी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट संदेश देना होगा कि कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पीड़ित युवक और उनके परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। परिवार ने बताया कि समाज में इस प्रकार की हिंसा बढ़ रही है और स्थानीय प्रशासन को इसमें सक्रिय होकर दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब उनका भरोसा सिर्फ प्रशासन और कानून व्यवस्था पर है, क्योंकि समाज में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। यह मामला देश में अल्पसंख्यक विरोधी घटनाओं की बढ़ती सूची में एक और कड़वा अध्याय जोड़ता है। उत्तराखंड जैसे पर्यटन और हिमालयी राज्य में भी इस तरह की हिंसा का होना, यह स्पष्ट संकेत है कि सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव अब केवल सीमित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। समाज विशेषज्ञों का कहना है कि इसे रोकने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार से मांग की है कि वे तुरंत जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार करें और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो यह घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी और देश में सामाजिक ताने-बाने को नुकसान होगा।

इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा और न्याय केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और समाज की सक्रिय भूमिका भी उतनी ही जरूरी है। पीड़ित युवक का इलाज अभी चल रहा है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समाज में सहिष्णुता को लेकर चेतावनी की घंटी बज रही है।

पाकिस्तान की साजिश नाकाम: अमृतसर में 200 करोड़ की हेरोइन और हथियार जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)। अमृतसर। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश को नाकाम करते हुए 200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हेरोइन और हथियारों की खेप बरामद की है। यह मामला हलका राजासांसी के गांव ओठियां में बुधवार देर रात सामने आया। पुलिस के मुताबिक, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई इस खेप में कुल 42.983 किलो हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, एक स्टार मार्क पिस्तौल और 46 जिंदा कारतूस पाए गए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अमृतसर के ही निवासी बताए जा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर रात दो युवक मोटरसाइकिल से हेरोइन और हथियार ले जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोपियों ने मौके पर मोटरसाइकिल छोड़कर फरारी पकड़ ली। सूचना मिलते ही हलका राजासांसी की इंचार्ज सोनिया मान भी मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक्स सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ग्रामीण पुलिस और ग्राम रक्षा समिति (VDC) की मदद से यह बड़ी खेप बरामद की गई। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान 42.983 किलो हेरोइन, चार हैंड ग्रेनेड, एक स्टार मार्क पिस्तौल, 46 जिंदा कारतूस और एक लावारिस मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित ड्रग तस्करी और हथियारों की खेप को भारत में पहुंचाने की कोशिश थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह खेप पाकिस्तान से काले पैकेटों में पैक होकर ड्रोन के माध्यम से भेजी गई थी। इस तरह की साजिशें न केवल कानून और व्यवस्था के लिए खतरा हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति को भी प्रभावित कर सकती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अमृतसर के रहने वाले हैं और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए उनकी गहन पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय तस्करी और हथियार आपूर्ति नेटवर्क की पड़ताल भी शुरू कर दी है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नशे और हथियारों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की पूरी जांच की जाएगी ताकि ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को पूरी तरह से रोका जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान से आने वाली इस तरह की ड्रग और हथियारों की खेपें न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित करती हैं, बल्कि सीमांत और ग्रामीण इलाकों में अपराध की घटनाओं को भी बढ़ाती हैं। इसलिए पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा और समाजिक सुरक्षा दोनों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।

इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस की सक्रियता को लेकर लोगों में संतोष है। वहीं, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में उनके सहयोगियों और खेप के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश जारी है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांव भेजा जंगली में रिटायर्ड IAS एनपी सिंह ने रखी 'तथागत ग्लोबल गुरुकुल' की नींव, दूरदराज के बच्चों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर

(जीएनएस)। बालोद, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के सुदूर आदिवासी गांव भेजा जंगली में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। रिटायर्ड आईएएस एनपी सिंह की पहल पर 'तथागत ग्लोबल गुरुकुलम' की नींव भूमि पूजन के साथ रखी गई। इस अवसर पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जीआर राणा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यह कार्यक्रम जकवार फाउंडेशन और तथागत ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। भूमि पूजन से पहले कार्यक्रम में राजा राव बाबा और कंकालीन माता की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनपी सिंह ने कहा कि इस गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के आदिवासी और ग्रामीण बच्चों को शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक गांवों के बच्चों को उच्च शिक्षा और सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा।

एनपी सिंह ने बताया कि भेजा जंगली में स्थापित यह गुरुकुलम देश के प्रमुख और प्रतिष्ठित स्कूलों के मानक के अनुरूप शिक्षा देगा। यहां बच्चों को न केवल अकादमिक शिक्षा बल्कि अच्छे संस्कार, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व विकास और करियर मार्गदर्शन भी मिलेगा। विशेष रूप से बच्चों को सेना और केंद्रीय बलों में करियर बनाने की तैयारी, रोजगार संबंधित पाठ्यक्रम और महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग से जोड़ने वाली ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को यहां पढ़ाई और सीखने का पूरा अवसर मिलेगा। गुरुकुलम में शिक्षा पूरी तरह निशुल्क होगी, ताकि हर बच्चे को सीखने और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिल सके। एनपी सिंह ने बताया कि विद्यालय का निर्माण कार्य फरवरी 2026 से शुरू होगा और इसे राजा राव पठार में राजा राव की पूजा के अवसर पर उद्घाटन का संकल्प लिया गया है। उनका मानना है कि इस गुरुकुलम के छात्र आगे चलकर आईएएस, आईपीएस, जज और अन्य महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचकर अपने गांव और देश का नाम रोशन करेंगे।

भेजा जंगली और आसपास के 10-12 गांवों के आदिवासी और ग्रामीण बच्चे इस गुरुकुलम से प्रत्यक्ष लाभान्वित होंगे। भूमि पूजन के बाद पूरे वनांचल क्षेत्र में खुशी का माहौल है और ग्रामीणों ने इस पहल को शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की सरपंच शीला यादव, पंच नागेश्वर सलाम, दिनेश यादव, बलराम गोटी सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे।

गांववासियों ने कहा कि यह गुरुकुलम बच्चों के जीवन में शिक्षा की अलख जगाने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। एनपी सिंह की यह पहल न केवल आदिवासी बच्चों के लिए अवसरों का द्वार खोलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह गुरुकुलम शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी और ग्रामीण बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है, जो उन्हें वैश्विक स्तर की शिक्षा के साथ-साथ जीवन कौशल, संस्कार और नेतृत्व क्षमता से भी लैस करेगा। भविष्य में तथागत ग्लोबल गुरुकुलम न केवल बालोद जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।